उत्तर प्रदेश

विशिष्ट करेंट अफेयर्स

फरवरी 2023

उत्तर प्रदेश 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ शीर्ष चार राज्यों में शामिल

• उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले चार राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने 'हर घर जल, 75 लाख नल' समारोह के रूप में उत्साह के साथ मनाया।

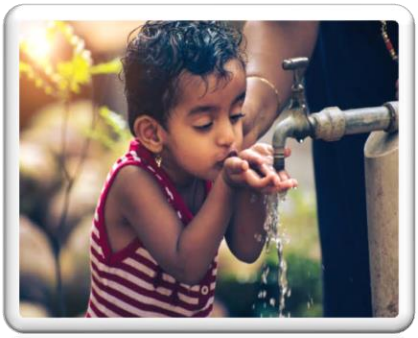

• उत्तर प्रदेश में विभाग की समस्त टीम को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए 75 इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

• इसके अलावा जल जीवन मिशन की दो साल की सफलतापूर्वक यात्रा पर आधारित फिल्म 'हर घर पानी, खुद निगरानी'का अनावरण व विभाग की उपलब्धियाँ गिनाती ई बुकलेट का विमोचन किया गया।

• कार्यक्रम में खासकर बुंदेलखंड में विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से गाँव-गाँव तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है इसको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मंचित किया गया तथा पूर्वी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुँचने से मिली खुशियों को सांस्कृतिक झलकियों से प्रस्तुत किया गया।

• जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने बहुत कम समय में बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से 75,26,740 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में चौथा स्थान हासिल किया है।

• गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से आगे बिहार 1.58 करोड़ से अधिक, महाराष्ट्र 1.06 करोड़ से अधिक और गुजरात 91 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्य हैं।

बुलंदशहर-खुर्जा के 55 गाँव यीडा में शामिल

• उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांव अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में शामिल हो गए हैं। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है।

• यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में इन गांवों के शामिल होने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा।

• यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा ज़िले आते हैं। अभी तक बुलंदशहर ज़िले के 40 गाँव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में थे।

• यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही एयरपोर्ट भी बन रहा है। लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब भी विकसित होगा। इस हब को रेलमार्ग से जोड़ने की योजना थी। इसके लिये प्राधिकरण को अपना दायरा बढ़ाकर दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग के पास तक ले जाना था। इसके लिये प्राधिकरण ने 55 गाँवों को शामिल करने की योजना बनाई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डी.जी. वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर डी.जी. वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल डी.जी. वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

• जी-20 कार्यक्रम के अंतर्गत इस मोबाइल डी.जी. वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

• यह डी.जी. वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित डिजिटल इंडिया अभियान की महत्त्वपूर्ण डिजिटल नव पहलों- 'माई गॉव', 'डिजी लॉकर', 'ई-हॉस्पिटल', 'ई-नाम', 'जेम पोर्टल', 'यू.पी.आई.', 'उमंग', 'जी.एस.टी.एन.', 'साइबर सुरक्षित भारत', 'आरोग्य सेतु'आदि को दिखाएगी।

• इस वैन में वी.आर. सेटअप भी है, जिसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार के डिजिटल एप्लीकेशन, जैसे यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप पर भुगतान, डिजिलॉकर के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना इत्यादि का वर्चुअल डेमो देख सकेंगे।

• उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत राशन की दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हुई है।

• भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के तहत खनन प्रबंधन के लिये 'माइन मित्रा' एवं अन्य तकनीकी अवसंरचनाओं का सृजन किया गया।

• इस वैन में 2 स्क्रीन, इंट्रैक्टिव क्विज के लिये हैं, जिस पर डिजिटल इंडिया व जी-20 के बारे में व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते है।

• इसी क्रम में प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और सक्षम बनाने के लिये, राज्य सरकार द्वारा 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के अंतर्गत 'डिजीशक्ति पोर्टल' के माध्यम से छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

• आगामी 5 वर्षों में कुल 2 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किये जाने का लक्ष्य है। अब तक 20 लाख युवाओं को नि:शुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन प्रदान किये जा चुके हैं।

• बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिये प्रेरणा पोर्टल विकसित किया गया है। तकनीक का बेहतर उपयोग करके मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, 1090- विमेन पावर लाइन हेल्पलाइन को समुचित रूप से क्रियान्वित कराया जा रहा है।

कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिये एसजेवीएनएल ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया

• केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है।

• कंपनी ने प्लांट लगाने के लिये प्राधिकरण से घाटमपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 एकड़ ज़मीन मांगी है। इस ज़मीन पर कंपनी करीब 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी।

• इस प्लांट के लगने से करीब 300 लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। वहीं, प्रदूषण रहित बिजली की वजह से पर्यावरण को लाभ होगा।

• एसजेवीएनएल के अतिरिक्त महाप्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी जालौन के काल्पी और उरई तहसील में 75-75 मेगावाट के प्लांट स्थापित कर रही है जिनमें काल्पी के परासन गाँव में स्थापित प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आ गया है।

• वहीं, कानपुर देहात के अकबरपुर में भी 50 मेगावाट का एक सोलर पॉवर प्लांट निर्माणाधीन है।

• उल्लेखनीय है कि सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली अन्य किसी माध्यम से पैदा होने वाली बिजली से सस्ती होती है।

• कंपनी सीधे तौर पर ओपन मार्केट के अलावा उद्योगों व कानपुर मेट्रो जैसे प्रतिष्ठनों को बिजली बेचने के लिये संपर्क करेगी।

न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

• सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलेजियम ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है।

• सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलेजियम ने केंद्र सरकार से की गई सिफारिश में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने से खाली हुए पद पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की नियुक्ति की जाए।

• उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर 3 अक्तूबर 2018 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किये गए थे। यहाँ के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति होने के नाते इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

• न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर का जन्म 22 नवंबर 1961 को हुआ था। उन्होंने दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से कानून में स्नातक किया है। 1984 में वे अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए।

• वे सेल, भारतीय स्टेट बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, कोटक महिंद्रा बैंक, रायपुर दुग्ध संघ, सीबीएसई और कई अन्य नगर निगमों के स्थायी वकील रहे हैं।

• उन्हें जनवरी 2005 में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वह सात साल के लिये मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल और पाँच साल के लिये स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के सदस्य थे।

• 31 मार्च 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वे पदोन्नत हुए। 21 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर अपने पद से रिटायर हो जाएंगे।

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट - 2023

• 12 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (यूपी जीआईएस-2023) का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ।

• यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3 दिन में कुल 33 लाख, 50 हज़ार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके साथ ही यहाँ पर कुल 19058 एमओयू साइन हुए। इससे करीब 93 लाख, 82 हज़ार, 607 लोगों को रोज़गार मिलेगा।

• राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा एवं एमओयू के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये 'निवेश सारथी'नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।

• उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय यूपी जीआईएस-2023 का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

• उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी इस समिट में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एशोसिएशन ने बाराबंकी में 30 हज़ार की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने के लिये प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है।

• यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतिम दिन यूके पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों ने सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। अब उत्तर प्रदेश मेडिकल और दवा क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को इस सेक्टर में 63,475 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। दवा और उपकरण से जुड़े कारोबार को लेकर कुल 156 करार अभी तक हुए हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों में अस्पताल खोलने का एलान किया है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी।

• उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्म और इको टूरिज्म के लिये 29,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

• उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 ,उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शुमार है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और निवेश हासिल करने के लिये दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नेताओं को सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिये इस मंच पर बुलाया जाता है।

• उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है, जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

• इस समिट में 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) की भागीदारी देखी गई।

• दिसंबर 2022 में यूपीजीआईएस 2023 के लिये राज्य सरकार ने 16 देशों और भारत के 8 प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किये थे, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और निवेश को बढ़ाया जा सके।

• इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसी कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएँ 'साझेदार देश'रहे हैं।

• ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसमें 28 हज़ार करोड़ के विभिन्न बड़ी कंपनियों की तरफ से विकास को लेकर एमओयू साइन किये गए थे।

उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर करेगा बिजली बैंकिंग

• उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर सभी क्षेत्रों में भरपूर निर्बाध बिजली देने के प्रयासों को फलीभूत करने के लिये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है।

• चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि बिजली बैंकिंग के तहत सर्दियों तथा सामान्य दिनों में जब राज्य में बिजली की मांग औसत अथवा कम रहती है, उस समय कॉरपोरेशन उपलब्ध अतिरिक्त बिजली जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के साथ ही एनटीपीसी को देगा। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने पर ज़रूरत के मुताबिक इस बिजली को इन राज्यों से वापस लिया जाएगा।

• गौरतलब है कि 2014 में राज्य में महज़ 1 करोड़ 42 लाख 64 हज़ार बिजली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 25 करोड़ पहुँच गए हैं। 2014 में बिजली की अधिकतम मांग, जो 12327 मेगावाट थी, वह 2022 में दोगुने से अधिक 26589 मेगावाट पहुँच गई है। बिजली सप्लाई के घंटों में भारी वृद्धि हुई है। ज़िला मुख्यालय तथा उद्योगों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, गाँवों को भी 6 घंटे अधिक बिजली मुहैया कराई जा रही है।

• उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलने से निवेशक भी उत्तर प्रदेश आने को आतुर नज़र आ रहे हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए भारी-भरकम निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आएगा। उद्योगों के आउटपुट से राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में तेज इजाफा होगा।

• माना जा रहा है कि दो से तीन साल के अंदर ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर पहुँच जाएगी। हालाँकि उद्योगों के आने के साथ ही पावर कॉरपोरेशन को आने वाले सालों में बिजली की मांग की संभावित वृद्धि का आकलन नए सिरे से करना होगा, जिसकी तैयारी कॉरपोरेशन ने शुरू कर दी है।

• कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज के मुताबिक बिजली बैंकिंग के बड़े फैसले के बाद पावर कॉरपोरेशन सर्दियों व आम दिनों में राज्य के पास उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को पावर एक्सचेंज से बेचेगा नहीं, बल्कि जिन राज्यों से करार हो रहा है, उन्हें दे देगा।

• उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर से 29 मिलियन यूनिट, तमिलनाडु से 61.56 मिलियन यूनिट का समझौता पहली बार किया है। कर्नाटक और एनटीपीसी से करार प्रस्तावित है। बैंकिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश से जुड़े राजस्थान ने पिछले वर्ष 449.6 मिलियन यूनिट का करार किया था। अब करीब चार गुना अधिक 1967.8 मिलियन यूनिट की बैंकिंग का करार किया है। मध्य प्रदेश से भी बैंकिंग का करार हुआ है।

• चेयरमैन का दावा है कि इस प्रयास से प्रदेश में बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्दियों में जब मांग कम रहती है, उस समय उत्पादन गृहों को पूरी क्षमता से चलाया जा सकेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों को अतिरिक्त बिजली चली जाएगी। बिजली बैंकिंग के तहत कॉरपोरेशन इन राज्यों को सरप्लस बिजली होने पर करार के मुताबिक तय बिजली देगा। ये राज्य जब उत्तर प्रदेश को ज़रूरत होगी तो ली गई बिजली वापस करेंगे।

• इसका लाभ यह होगा कि जब राज्य में जून से सितंबर के बीच बिजली की मांग अधिकतम होती है उस समय भी बिजली की कोई किल्लत नहीं होगी। पावर एक्सचेंज से 12 रुपए और अधिक की दर से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। हमेशा गर्मी के दिनों में पावर एक्सचेंज में बिजली का रेट बहुत अधिक रहता है।

• चेयरमैन ने बताया कि 7413 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाइयों से बिजली का उत्पादन 2025-26 तक शुरू हो जाएगा। 2023-24 के अंत तक इसमें से 5000 मेगावाट की इकाइयाँ चलने लगेंगी।

• 2021-22 में 927 करोड़ रुपए तथा 2022-23 में अब तक 91 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जा चुकी है। 2030 तक राज्य में बिजली की अनुबंधित उत्पादन क्षमता 40392 मेगावाट तक की जानी है। 2023 में अनुबंधित उत्पादन क्षमता 32356 मेगावाट तक ले जाने की है।

• 2022-23 में बिजली की अधिकतम मांग 26589 मेगावाट तक पहुँची जबकि 2014 में अधिकतम मांग 12327 मेगावाट ही थी। 2023-24 में अधिकतम मांग 27776 मेगावाट तक पहुँचने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 को मंजूरी

• उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण के लिये वातावरण तैयार करने और विभिन्न आवश्यक संसाधनों का शूटिंग के लिये समग्र विकास करने हेतु फिल्म नीति लागू की है।

• उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिये राज्य में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्म में राज्य के कलाकारों को किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी।

• फिल्म निर्माण के लिये कुल शूटिंग दिवस के दो तिहाई दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर दो करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।

• नोएडा में एक हज़ार एकड़ में फिल्मसिटी बनाई जा रही है। प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी फिल्म निर्माण की सुविधाओं के विकास की योजना है। फिल्मसिटी में बनने वाली फिल्मों को भी इस नीति के अनुसार रियायत दी जाएगी।

• फिल्म नीति के तहत ये सुविधाएँ भी मिलेंगी - शूटिंग के लिये सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस, पर्यटन अतिथि गृह की व्यवस्था की जाएगी। विभागों के स्तर से आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी किया जाएगा।

• आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस व होटल में कमरे के किराए पर 25 फीसदी छूट दी जाएगी।

• प्रदेश में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के लिये निर्माण पर 50 फीसदी, हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पर फिल्म बनाने पर 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसमें कुल शूटिंग दिवस के कम से कम 50 फीसदी यूपी में शूटिंग होने पर एक करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी।

• वेब सीरीज की शूटिंग पर प्रति एपिसोड 10 लाख या एक करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वेब फिल्म में पाँच मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में बनेगा हाई टेक मिलिट्री अस्पताल

• उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले और राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण होगा।

• मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण करने का उद्देश्य देश की सेवा में जुटे सैनिकों, सैन्य परिवार के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

• उल्लेखनीय है कि करीब एक दशक पूर्व मध्य कमान की ओर से पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मिलिट्री अस्पताल की आवश्यकता जताई गई थी। वर्ष 2011-2012 में इसके लिये एक प्रस्ताव भी बनाया गया था।

• वर्ष 2012-2013 में यह प्रस्ताव पहले मध्य कमान और उसके बाद रक्षा मंत्रालय भेजा गया। अब रक्षा मंत्रालय ने मेरठ में रक्षा भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल के निर्माण के साथ राजधानी लखनऊ में भी अत्याधुनिक मिलिट्री अस्पताल को मंजूरी दे दी है, जो मध्य कमान का सबसे बड़ा मिलिट्री अस्पताल होगा।

• मेरठ में यह मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण 379 करोड़ रुपए की लागत से होगा। यह अस्पताल 545 बेड का होगा।

• मल्टी सुपर स्पेशिलिटी मिलिट्री अस्पताल के लिये सेना ने मेरठ के भगत चौक से औघड़नाथ मंदिर के बीच ज़मीन पूर्व से ही चिह्नित कर रखी है। सेना की ओर से प्रस्तावित जमीन पर पूर्व में ही 'साइट फॉर एमएच'का बोर्ड लगा दिया गया था। इस नए मिलिट्री अस्पताल से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 ज़िलों के सैनिकों, पूर्व सैनिक और उनके परिवार लाभान्वित हो सकेंगे।

बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए DCGI

• उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किये गए हैं।

• डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी डॉ. वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो गया था।

• गौरतलब है कि डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी के नाम से 250 से ज्यादा पेटेंट दवाएँ भी हैं।

• डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव-सह-वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पिछले महीने डीसीजीआई के पद के लिये उनके नाम की सिफारिश की थी। इसको संज्ञान लेकर मंत्रिमंडल समिति ने आदेश पारित किया है।

• विदित है कि डीसीजीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का प्रमुख पद होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार होता है। इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और क्लीनिकल ट्रायल को विनियमित करने का भी अधिकार होता है।

उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन

• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गाँव में 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

• इस अवसर पर नितिन गडकरी ने बलिया-आरा के बीच 1500 करोड़ रुपए की लागत से 28 किलोमीटर ग्रीनफील्ड स्पर रोड के माध्यम से नए संपर्क मार्ग की भी घोषणा की।

• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के बनने से अब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ से पटना केवल साढ़े चार घंटे में पहुँचा जा सकेगा। बलिया से बक्सर आधे घंटे में, बलिया से छपरा एक घंटे में और बलिया से पटना डेढ़ घंटे में पहुँचा जा सकता है।

• उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार के छपरा, पटना, बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

• इस एक्सप्रेस-वे से बलिया के किसानों की सब्जियाँ लखनऊ, वाराणसी और पटना की मंडियों में आसानी से पहुँच सकेंगी। सब्जी उत्पादक किसानों को वाराणसी, गाजीपुर और हल्दिया के तीन मल्टी मॉडल टर्मिनल का सीधा लाभ मिलेगा।

• केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 130 करोड़ रुपए की लागत से चंदौली से मोहनिया तक ग्रीनफील्ड सड़क बनेगा। यह सड़क उत्तर प्रदेश के चंदौली और बिहार के कैमूर ज़िले को दिल्ली-कोलकाता जी.टी. रोड से जोड़ेगी।

• इसी तरह सैदपुर से मरदह तक सड़क बनेगा, जिससे सैदपुर होते हुए मऊ से वाराणसी का सीधा संपर्क हो जाएगा।

• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही आजमगढ़ ज़िले के पिछड़े इलाकों को भी नया कनेक्टिविटी मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया 6.90 लाख करोड़ का बजट

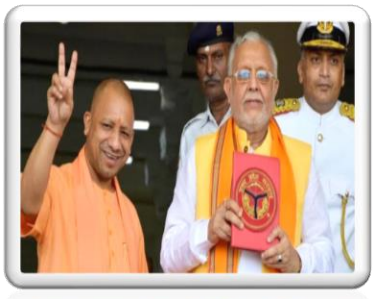

• उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी 2023 को राज्य का बजट पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया।

• उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया।

• इस बजट का उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण करना और

उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डालर की अर्थव्यवस्था बनाना है। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

यूपी बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: 1050 करोड़ आवंटित रुपये

• राज्य सरकार ने निराश्रित विधवाओं के लिए 4,032 करोड़ रुपये आवंटित किए

• सामूहिक विवाह: 600 करोड़ रुपये आवंटित। यह योजना सभी वर्ग की लड़कियों के लिए है और उनकी शादी में मदद करेगी।

• स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना: टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए; 3600 करोड़ रुपये आवंटित

• सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये आवंटित

• सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ रुपये

• कृषि विपणन सुविधाओं के निर्माण के लिए 3,473 करोड़ रुपये

• ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,525 करोड़ रुपये

• रेलवे ओवरहेड ब्रिज के निर्माण के लिए 1,850 करोड़ रुपये

• राज्य राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए 2,588 करोड़ रुपये

• जिला सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 2,538 करोड़ रुपये

• धर्मार्थ मार्ग: धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये

• विवाह अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित। यह अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए है

• प्रदेश में सड़कों के रख-रखाव के लिए स्टेट रोड फंड से 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

• निवेश का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये रखा गया है

• पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपये प्रस्तावित

• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपये प्रस्तावित

BYJU'S EXAM PREP